Business Standard

26 January, 2017

# Retail players on a patriotic high

## Online, offline firms hope to cash in on last major discount sale this festive season

KARAN CHOUDHURY
New Delhi, 25 January

Online and offline Republic Day sales could collectively reach ₹1,500 crore as experts see demand picking up after demonetisation.

Online marketplaces Amazon, Flipkart and Snapdeal, and brick and mortar players and mall owners have all organised sales, where the emphasis is on going cashless. During last year's festive season, they ended up with $1.5 billion in sales or order value.

Republic Day sales are the last of the major discounts in the festive cycle in the retail industry.

Experts were anxious about footfalls at malls and high-street stores after demonetisation saw sales tumbling. Industry body Assocham estimates retailers will end up earning over ₹1,500 crore this weekend.

"We had an Epic Sales weekend over January 20-22 as a lead-up to Republic Day. The Republic Day weekend is like the Thanksgiving weekend now, so brands put their best foot forward in terms of deals and services," said Pushpa Bector, executive vice-president and head, DLF Premium Malls. She added demonetisation-specific sales by brands took place almost immediately after its announcement. This was designed to encourage the public to spend digitally. "We expect footfalls to grow 10 per cent this year over last year and overall sales to grow 12-14 per cent," Bector said.

Future Group's Big Bazaar, which organises major sales during the Republic Day week, is adding new services such as pre-booking at cash counters. "Customers have to pay ₹100 online to book a slot for cashing out. This is returned when they pay for the goods. We have also stepped up downloads of the Future Pay app and are doing a lot of home delivery," said Sadashiv Nayak, chief executive officer, Big Bazaar.

According to experts, discounts and a positive market sentiment are helping retailers get back on track.

"The markets started recovering by the end of November as organised retail was able to adopt various digital means of payments. Electronics and jewellery are the two sectors that are still recovering. The sales are providing an added boost, now everyone is waiting for the budget," said Kumar Rajagopalan, chief executive officer, the Retailers Association of India.

The Amazon Great Indian Sale witnessed a surge in digital payments and people using the card-on-delivery option.

Amazon's new customer acquisition rate matched the peak Diwali shopping season.

### R-DAY SALES MAY TOUCH ₹1,500 CR

**amazon.in**

- Significant growth in Amazon Pay balance usage, with 30X customers loading money into the Amazon Pay balance as compared to a normal day
- New customers who adopted Amazon Pay grew **360%**
- Over 2,200 sellers witnessed their biggest sale day ever during the event
- Sellers from Tier-II and below geographies witnessed growth of over **135%** as compared to a normal day
- Number of sellers in the 10-million club grew over **30%** as compared to last year

**snapdeal**

- Snapdeal offered up to **70%** discount on gadgets
- Around **15%** instant discount and earn 5X reward points by using HDFC Bank credit cards

**BRICK AND MORTAR RETAIL**

Future Group offering **5%** to **30%** discount.

Business Standard (Hindi) 26 January, 2017

# खरीद तंत्र की गणतंत्र उम्मीद

**करण चौधरी**
नई दिल्ली, 25 जनवरी

**इस** साल गणतंत्र दिवस पर ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री कुल मिलाकर 1,500 करोड़ रुपये की हो सकती है। विशेषज्ञों ने कहा कि अब नोटबंदी के बाद मांग जोर पकड़ रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुदरा क्षेत्र में त्योहारी सीजन के बाद बड़ी छूट दी जा रही है। तीन बड़ी ऑनलाइन कारोबारी कंपनियों स्नैपडील, एमेजॉन और फ्लिपकार्ट बड़े पैमाने पर बिक्री कर रही हैं, वहीं बाजारों में मौजूद दुकानों, मॉल मालिकों और अन्य संगठित खुदरा बिक्रेताओं ने नकदी रहित पर जोर दिया है। पिछले साल के त्योहारी सत्र के दौरान 1.5 अरब डॉलर की बिक्री हुई थी।

विभिन्न मोहल्लों की दुकानों में पिछले 2 महीने से ग्राहकों की आमद कम होने से विशेषज्ञ चिंतित थे। अब ग्राहक स्टोरों की ओर आकर्षित हुए हैं। उद्योग संगठन एसोचैम के अनुमान के मुताबिक इस सप्ताहांत खुदरा बिक्रेता 1,500 करोड़ रुपये का कारोबार करेंगे।

## बिक्री तेज

- 1,500 करोड़ रुपये की हो सकती है ऑनलाइन व ऑफलाइन बिक्री
- अब नोटबंदी के बाद मांग जोर पकड़ रही

डीएलएफ प्लैटिनम मॉल की कार्यकारी उपाध्यक्ष व प्रमुख पुष्पा बेक्टर ने कहा, 'डीएलएफ के प्रीमियम मॉलों में हमने 20-22 जनवरी तक बेहतरीन कारोबार किया है। गणतंत्र दिवस का सप्ताहांत हमारे लिए बेहतर रहा है। सौदों और सेवाओं के मामले में सप्ताहांत पर ब्रांडों ने बेहतरीन पेशकश की। एमओआई के स्तर पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिक्री और लोगों की आवक के हिसाब से 4 दिनों तक बेहतरीन सप्ताहांत रहेगा।' उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से ब्रांडों की बिक्री पर असर पड़ा था। यह साल हमारे लिए उत्साहजनक है और लोग डिडिटल भुगतान करने लगे हैं। बेक्टर ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि पिछले साल की तुलना में मॉलों में आने वालों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। साथ ही कुल बिक्री 12 से 14 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।'

गणतंत्र दिवस के पूरे सप्ताह के दौरान फ्यूचर समूह के बिग बाजार ने छूट दी। साथ ही कंपनी ने प्री बुकिंग व बगैर नकदी वाले काउंटर भी शुरू किए, जिससे ग्राहकों को कतारों से बचाया जा सके। बिग बाजार के सीईओ सदाशिव नायक ने कहा, 'कैशिंग आउट स्लॉट बुक करने के लिए उपभोक्ताओं को 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान करने होते हैं। जब वे सामान खरीदते हैं तो इसे वापस कर दिया जाता है। साथ ही हम लोगों ने फ्यूचर पे ऐप डाउनलोड करने की दिशा में बढ़े हैं और बड़े पैमाने पर होम डिलिवरी भी कर रहे हैं।' विशेषज्ञों के मुताबिक छूट और बाजार के सकारात्मक माहौल की वजह से खुदरा बिक्रेताओं का काम पटरी पर आया है और यह बजट में सरकार की ओर से की गई घोषणा के पहले हुआ है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। रिटेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया के कुमार राजगोपालन ने कहा कि नवंबर के आखिर से बाजार की स्थिति में सुधार होने लगा था क्योंकि संगठित खुदरा में डिजिटल भुगतान को स्वीकार किया जाने लगा था। इलेक्ट्रॉनिक्स व आभूषण दो बाजार ऐसे हैं, जहां अभी भी कारोबार को गति पकड़ना बाकी है।

Rashtriya Sahara

26 January, 2017

# स्वास्थ्य सेवा को जीएसटी से बाहर रखने का सुझाव

- टैक्स बढ़ने से पहुंच से बाहर हो जाएंगी स्वास्थ्य सेवाएं
- फिलहाल सेवा कर के दायरे से बाहर हैं यह सेवाएं
- कई जरूरी दवाएं भी हैं सेवा कर के दायरे से बाहर
- खाद्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है हेल्थ

■ नई दिल्ली।

उद्योग मंडल एसोचैम ने स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर को (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। उसका मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी।

एसोचैम-टेसाई शोध पत्र में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है और जीएसटी के लागू होने के बाद कम से कम दस साल तक इसे इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। शोध पत्र में कहा गया है कि यह क्षेत्र समाज की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करता है और इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। अन्यथा चिकित्सा सुविधाएं महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी।

एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा, 'बड़ी संख्या में खाद्य उत्पाद और आम आदमी के इस्तेमाल की अन्य आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। स्वास्थ्य सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य है।

यह खाद्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। ऐसे में इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का मामला बनता है।' सरकार का जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का इरादा है। ■ भाषा

Pioneer (Hindi)

26 January, 2017

# जीएसटी के दायरे से बाहर हो स्वास्थ्य सेवा

नई दिल्ली। उद्योग मंडल एसोचैम ने स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर को (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। उसका मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी। एसोचैम-टेसाइ शोध पत्र में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है और जीएसटी के लागू होने के बाद कम से कम दस साल तक इसे इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। शोध पत्र में कहा गया है कि यह क्षेत्र समाज की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करता है और इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। अन्यथा चिकित्सा सुविधाएं महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा, बड़ी संख्या में खाद्य उत्पाद और आम आदमी के इस्तेमाल की अन्य आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। स्वास्थ्य सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। यह खाद्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। ऐसे में इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का मामला बनता है। सरकार का जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का इरादा है।

Naya India 26 January, 2017

# स्वास्थ्य सेवा जीएसटी से बाहर रखी जाए: एसोचैम

**नई दिल्ली, भाषा।** उद्योग मंडल एसोचैम ने स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु व सेवा कर को :जीएसटीः के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। उसका मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी। एसोचैम-टेसाइ शोध पत्र में कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है और जीएसटी के लागू होने के बाद कम से कम दस साल तक इसे इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। शोध पत्र में कहा गया है कि यह क्षेत्र समाज की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करता है और इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। अन्यथा चिकित्सा सुविधाएं महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी। एसोचैम के महासचिव डी एस रावत ने कहा, बडी संख्या में खाद्य उत्पाद और आम आदमी के इस्तेमाल की अन्य आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।